



लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? जानिए पूरा घटनाक्रम

प्रिय पाठकों, लखीमपुर की घटना कई कारणों से चर्चा में है। एक किस तरह नेतागण प्रजा को अपनी नीची नजरों से देखते हैं, किस तरह पुलिस और प्रशासन अपने नेताओं को बचाती है और बेकसूरों की जानों को पानी से भी सरता समझती है। हम आप पाठकगणों को पूरी कहानी बताते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से 70 किमी दूर तिकोनिया इलाके में 3 अक्टूबर को दोपहर करीब तीन बजे हिंसा हुई। इस हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हो गई।

तिकुनिया में किसान काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। डिप्टी सीएम को रिसीव करने जा रही गाड़ियों का काफिला जब तिकुनिया से निकला, तो प्रदर्शनकारी किसानों से उनकी झड़प हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि शर्जिय मिश्रा के बेटे के इस काफिलेश ने किसानों को कुचल दिया। हिंसा के बाद प्रशासन के सख्त कदम उठाते हुए लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू कर दी। इसके अलावा इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। स्कूल-कॉलेज भी अगले आदेश तक बंद हो गए। इसके अलावा बाहरी लोगों के जिले में आने जाने पर रोक लगा दी गई है। उधर विपक्षी नेताओं में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेता लखीमपुर खीरी के दौरे पर निकले, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक लिया।



आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया। इसके बाद यूपी में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी नेता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफतारी की मांग कर रहे हैं। दरअसल, दंगल का ये कार्यक्रम तिकुनिया से चार किमी दूर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पैतृक गांव बनवीरपुर में ही था।

घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खिलाफ हत्या, गैर इरादतन हत्या, दुर्घटना करने और



बलवा की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इसी एफआईआर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी का भी नाम शामिल है, धारा 120 वी के तहत केस दर्ज हुआ है। आपराधिक घटनाक्रम करने का भी आरोप है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। दोपहर को उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव बनवीरपुर में दंगल कार्यक्रम में शिरकत होने जाना था। अजय मिश्रा उनके साथ ही मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्रा रविवार को दोपहर करीब 1.30 बजे आपने काफिले के साथ लखीमपुर से

बनवीरपुर के लिए निकले थे। उन्हें रिसीव करने के लिए बनवीरपुर से तीन गाड़ियां निकली थीं। ये गाड़ियां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की बताई जा रही हैं।

लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से किसान नेता यहां लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हिंसा के करीब 24 घंटे बाद प्रशासन और किसान नेताओं के बीच समझौता हो गया। मृतक किसानों के पार्थिव शरीरों को घटना स्थल से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, वहीं किसान भी अब अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर बढ़ने लगे हैं। किसानों की मांग मानते हुए यूपी सरकार ने मृतकों को 45 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 10 लाख का मुआवजा देने का एलान किया है। साथ ही इस पूरे घटना क्रम की एक रिटार्ड हाई कोर्ट जज के द्वारा ज्यूडिशियल जांच आर्डर की गई है। इसके अलावा मृतकों के परिवार के एक सदस्य को उसके योगिता के अनुसार लोकल स्थर पर नौकरी दी जाएगी।

सरकार और नेतागण यह समझती है कि जान लेना, और जान की कीमत सांत्वना के नाम पर कुछ मुआवजा या नौकरी का लालच दिया जाता है। हमारा सवाल है कि क्या जान की कोई बदला हो सकता है? सरकारें चाहे आन्दोलन को कुचले, गैर जरूरी कानून बनाएं लेकिन हम यह कहते हैं अन्याय कब तक...
—टाइम्स ऑफ़ पीडिया

Editor's Desk

लोकतान्त्रिक देश में अलोकतान्त्रिक व्यवस्था



देश में पिछले कुछ वर्षों की चर्चित घटनाओं को मिसाल के तौर से पेश कर रहा हूँ, जिनको भूलाये जाने के लिए आये दिन नए मुद्दे खड़े किये जाते हैं, और मुद्दे के बाद मद्दे बनाये रखना अक्सर प्रायोजित होता है.... जैसे

राम मंदिर पर एक तरफा आस्था के आधार पर आया फैसला, फैसला सुनाने वाले जज को राज्य सभा की मेम्बरशिप, उमर गौतम साहब की गिरफतारी, उनके पक्ष में सैकड़ों टपकमवे और गवाहियां मौजूद, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफतारी, मामले में सैकड़ों Videos उनके पक्ष में मौजूद Love जिहाद, Corona जिहाद, चूड़ी जिहाद, न्यू जिहाद जैसे बे सरो पा मुद्दे क्यों लाये गए।

शाहीन बाग मूवमेंट चलाने वालों ने BJP Join कर ली, क्या वो भी कोई Trial था?

11 माह J&K में internet नहीं, लोगों ने मत्यों को अपने घरों में दफनाया, प्रायोजित दिल्ली दंगा, असल मुजरिम आज भी आजाद कोई चर्चा नहीं, हाथरस में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म फिर निर्मम हत्या और बाप की इजाजत के बिना चिंता का रात में अंतिम संस्कार का मामला खामोश, आखिर ये सब क्यों?

जम्मू में 8 साल की आसिफा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और निर्मम हत्या बैम का कुछ नहीं पता ये सब मुद्दों की वो परतें हैं जो एक पर एक चढ़ाई जाती हैं।

RAFFAIL डील पर राहुल गांधी का सरकार को खुला challenge.

पहलु खान, आसिफ, अखलाक, रक्खर उर्फ अकबर, पालघर साधु महाराज लिंगिंग ये सब मुद्दे खामोश, हरियाणा के बल्लभगढ़ निकिता हत्या काण्ड मामला भूल गए।

बुलंदशहर स्थाना के Inspector सुबोध कुमार हत्या काण्ड के आरोपी जमानत पर रिहा, देश ने खोया था एक इमानदार Police Officer, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या

द्वारा BANK लूट और फरारी मामला सब खामोश।

पुलवामा आतंकी हमला 14जी सितम्बर 2019 क्या हुआ आतंकियों का, कौन थे आतंकी कुछ नहीं पता और जनता भी भूल गयी।

बिहार के मुजफ्फरपुर hospital काण्ड 109 मासूम बच्चों की मौत, याद है या भूल गए।

कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लाशों को गंगा में बहा दिया गया, कुत्तों ने नोचा लाशों को क्यों हुआ ऐसा हाल, कौन था इस जुर्म के लिए जिम्मेदार, क्या इस पर सरकारों का जवाब? कुछ नहीं

अफगानिस्तान से आई हेरोइन जो अडानी मुंद्रा पोर्ट पर उत्तरी जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपये आंकी गयी थी और अब आर्यन खान Narcotics मामले के बाद रप्ता रप्ता भूला दिया जाएगा इसको भी, और अब जल्द ही खीरी लखीमपुर मुद्दा भी आप भूल जायेंगे, और फिर कोई भड़कता मुद्दा आपके सामने होगा....

सवाल यह है की देश में सरकारों के failure और नाकामी को उजागर करने और पाखंडी नेताओं को कब सिखाओगे सबक? चुनाव के आते आते देश धूर्षीकरण और साम्राज्यिकता के नशे में डूब जाएगा या डुबा दिया जाएगा और देश में हर आने वाला चुनाव जो लोकतान्त्रिक पर्व होता है इसको अलोकतान्त्रिक तरीकों से मनाया जाएगा।

भारत को 2019 के लिए सूचकांक में 51वें स्थान पर रखा गया है। 2018 में भारत 41वें स्थान पर था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत प्रशासित कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने, असम में एनआरसी पर काम शुरू होने और फिर विवादित नागरिकता कानून, सीएए की वजह से नागरिकों में बढ़े असंतोष के कारण भारत के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई।

दोस्तों धरातल पर जनता की भागीदारी की कमी की वजह से ही हमारा लोकतांत्र महज एक 'चुनावी लोकतंत्र' बनकर रह गया है। चुनाव में मतदान का इस्तेमाल एक अधिकार के रूप में नहीं, एक कर्तव्य के रूप में किया जाने लगा है। जिबाकि जनता की भागीदारी की पेपरों में काफी चर्चा है जो निराधार है।

लोक तंत्र की चौपाल यानी संसद भवन को Centre Vista Redevelopment Project के तहत परिवर्तित करने से पहले लोकतान्त्रिक व्यवस्था की जड़ों को अगर मजबूत कर लिया जाता तो यह जयादा देश के हित में होता, दुनिया में जम्मूरी निजाम यानि Democracy का निजाम खिलाफत का एक विकल्प तसव्वुर किया जाता है।

जिस Centre Vista की बुन्यादों को खोदने के लिए पुराने Lutyens Zone को खदान में बदल दिया गया है, दुनिया की कई खूबसूरत sites में से एक Site यह भी थी जिसकी तस्वीरें दुनिया भर से आने वाले सैलानी अपने कैमरों में केंद्र करके ले जाते रहे हैं।

लगभग 14 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले इस Vista Project को 2024 तक पूरा कर लिए जाने का अनुमान है, लेकिन इस नए Project की बुन्यादों में तारिख के कई बाब दफन हो रहे हैं। जबकि नए भवन की शक्ल में कुछ ऐसे गुम्बद भी होंगे जो शायद लोकतान्त्रिक व्यवस्था की मिस्राम होती कहानी को भी बयाँ करेंगे, लोकतांत्र और आजादी की सच्ची कहानी की तारीख मिटा दी जायेगी जिसके लिए लाखों स्वतंत्रता सैनानियों और आजादी के मतवालों ने अपने जान की आहुति देकर उसको लिखा था। और उसके बाद एक ऐसा सूर्य उदय होगा छाँ प्प घटकं प का ज

GAIL's Hawa Badlo initiative launches School Warriors 2.0 contest

New Delhi : Under its clean air initiative Hawa Badlo, GAIL (India) Limited has launched the second edition of School Warriors contest for creating awareness against air pollution

amongst students and the school community, including parents and teachers.

The School Warriors 2.0 contest aims at connecting with school students who are cur-

rently at health risks due to constant rise in pollutants in the air.

Through the online Hawa Badlo School Warriors 2.0 contest, the students will be given a chance to showcase their creative views on air pollution by uploading short videos, art forms, essays with ideas and their corrective suggestions against air pollution which can be submitted digitally on the School Warriors 2.0 microsite. (<http://schoolwarrior2.changetheair.org/>).

The participants can also plant saplings and upload pictures of them taking care of the plants. The entries can be uploaded till November 20, 2021 and the best entries will win prizes in various categories.

The first edition of School Warriors contest had more than five million reach on digital platforms. The contest got around 3,000 entries from across India.

The Hawa Badlo initiative is in line with the environmental responsibility of GAIL which is an integral part of its vision statement. It aims at improving the air quality with collective societal effort to bring substantial change in the quality of air for better environment and better lives.

-Report : Sunit Narula

Dismissal of the Union Minister of State for Home and Rs 50 lakh each to the families of martyr farmers and journalists by the Punjab & Chhattisgarh govt.



Congress has described the victory of democracy and defeat of the arrogant government for the permission given to former Congress president Rahul Gandhi and general secretary in-charge of UP, Priyanka Gandhi to visit Lakhimpur. Naseemuddin Siddiqui, former

minister and chairman of UPCC media department has said that the arrogance of the Yogi government collapsed in front of the Satyagraha of Mrs. Priyanka Gandhi and Mr. Rahul Gandhi. In Uttar Pradesh, not the constitution, the union propounded Yogi rule has made life difficult for the people, but under the leadership of Priyanka Gandhi, the Congress, from the tribal massacre of Umbha to Unnao, Hathras to Lakhimpur, has brought justice to the victims by vocally raising the voice of the general public.

The press statement issued by Naseemuddin Siddiqui strongly condemned the detention of Chief Ministers of Punjab and Chhattisgarh and Rahul Gandhi at Lucknow airport. He said that there is no part of humanity in the government which crushed farmers and journalists and killed them

Siddiqui said that the Congress party is not going to be afraid of the dictatorial government. Priyanka Gandhi's Satyagraha has paved the way for counteracting injustice by giving new energy to the struggle against arrogance. He said that the announcement of assistance of Rs 50 lakh each to the families of martyr farmers and journalists by the Punjab and Chhattisgarh government is a commendable step.

Priyanka ji's Satyagraha compelled the government to end illegal detention to allow them to meet the families of the martyr farmers. Mr Siddiqui said that the justice war is not over yet. Until the dismissal of the Union Minister of State for Home and the arrest of the culprits of the massacre, the struggle of the Congress will continue.

-S.A. Shah

NOTICE:
Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper.
Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to inaccuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

Ramayan's Raavan aka Arvind Trivedi passes away at 82



Ramayan's Raavan aka Arvind Trivedi passes away at 82; Sunil Lahri, Dipika Chikhlia & others condole

Ramayan's Raavan aka Arvind Trivedi passes away at 82; Sunil Lahri, Dipika Chikhlia & others condole.

Senior actor Arvind Trivedi who played the crucial role of Raavan in Ramanand Sagar mythological show 'Ramayan' passed away on Tuesday night.

-News Agency

हैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर ऑनलाइन परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार

सोनीपत: हैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर ऑनलाइन परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को एसटीएफ ने शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। वह दुबई भागने की फिराक में था। गिरफ्तार आरोपी सेक्टर-23 का रहने वाला विकासदीप दहिया है। एसटीएफ ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है। उसे रविवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं एसटीएफ गिरोह के सात सदस्यों से बरामद 1200 कंप्यूटर व छह लैपटॉप को पंचकूला लैब भेजकर जांच कराएगी।

एसटीएफ सोनीपत प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश देशवाल ने बताया कि एसटीएफ ने हैकिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर नौकरी लगावाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इनमें मूलरूप से गांव गोरड फिलहाल अपेक्षा ग्रीन मुरथल निवासी अशोक कुमार उर्फ शौकी, मूलरूप से गोरड फिलहाल पटेल नगर

निवासी मोनू कुमार उर्फ डाक्टर, गोरड निवासी आशीष, जयपुर के मोतीनगर निवासी आकाश, राजस्थान के दोसा कोड़ला के गौरी व जयपुर के पानावाला के आकाश कुमार व जींद के श्यामलो निवासी आशीष था। इनको अदालत में पेश कर आठ दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

इनसे पूछताछ के आधार पर एसटीएफ की टीम ने शनिवार को गैंग के मास्टरमाइंड विकासदीप दहिया को दिल्ली एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ की कार्वाई के बाद से वह फरार हो गया था। आरोपी दुबई भागने की फिराक में था। वहीं एसटीएफ को तीन अन्य आरोपियों की जानकारी मिली है। उनकी तलाश में रोहतक, दिल्ली व बहादुरगढ़ में छापा मार कार्वाई की गई है।

गिरोह के सदस्यों से 1200 कंप्यूटर, 130 हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कई ब्लैंक चेक, छह लैपटॉप व 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। इनको जांच के लिए



पुलिस की फॉरेंसिक लैब पंचकूला में भेजने की तैयारी की जा रही है। जिससे अन्य सुबूत जुटाए जा सके। पेपर सॉल्व करने वालों के साथ लैब के आईटी हेड से करता था सेटिंग।

गिरफ्तार आरोपी विकासदीप दहिया पर आरोप है कि वह पेपर सॉल्व करने वाले युवकों की तलाश करता था। वह पेपर से पहले उनसे संपर्क कर उन्हें तैयार कर लेता था। इसके साथ ही वह परीक्षा केंद्र की लैब के आईटी हेड से

सेटिंग करता था। जिसके बाद परीक्षा पास कराने में आसानी होती थी।

ऑनलाइन परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। वह दुबई भागने की फिराक में था। उससे गिरोह के अन्य राज्यों में कार्य करने वाले शातिरों की जानकारी मिल सकेगी। उसको न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है।

चार रिशेदार मिलकर बसों में सवार पात्रियों की करते पै जेब तराश

करनाल में चार रिशेदार मिलकर बसों में सवार यात्रियों की जेब तराश कर फरार हो जाते थे। ये बस स्टाप पर ही यात्रियों की जेब में नकदी होने का अंदाजा लगा लेते थे और फिर भीड़ का फायदा उठा वारदात को अंजाम दे देते थे। बैंक के आसपास भी वारदात करते थे। आरोपियों में दो सगे भाई शामली, उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं जबकि दो आरोपित ताऊ-भतीजा हैं। पुलिस ने आरोपित मामा-भांजा को गिरफ्तार किया तो यह राज खुला। बाकि दो आरोपित अभी फरार हैं, जो रिश्ते में जीजा-साला लगते हैं। चारों मिलकर करनाल व कुरुक्षेत्र एरिया में जेब तराशने की 13 वारदातें कर चुके थे।

बता दें कि पुलिस को बसों में यात्रियों की जेब से नकदी चुरा लेने की वारदात किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिन पर संज्ञान लेते वारदातों को सुलझाने का जिम्मा डिटेक्टिव स्टाफ को सौंपा गया। इंचार्ज हरिजंद्र सिंह सिंह ने एएसआई हिम्मत सिंह की अध्यक्षता में टीम बनाई, जिसने आरोपित सागर वासी गांव नौरता जिला करनाल व रवि वासी गांव श्यामगढ़ी जिला शामली, उत्तर प्रदेश को सात अक्टूबर को इंद्री से गिरफ्तार किया।

उन्हें चार दिन के रिमांड पर लिया गया तो पूछताछ में माना कि उनके साथ सुंदर वासी गांव नौरता, जो सागर का ताऊ है व श्यामगढ़ी जिला शामली उत्तर

प्रदेश, जो रवि का सगा भाई है, के साथ मिलकर 13 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अभी तक फरार सुंदर व श्यामगढ़ी का काबू करने के लिए टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार रवि व श्यामगढ़ी आरोपित सागर के मामा लगते हैं। जांच में पता चला है कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी करनाल व कुरुक्षेत्र में जेब काटने के करीब सात मामले दर्ज हैं। इन मामलों में गिरफ्तार हो चुके थे और अभी जमानत पर थे।

डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज हरिजंद्र ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने माना कि वे सभी किसी एक बस स्टाप पर मौजूद रहते थे और वहां रहकर जिस व्यक्ति की जेब भारी होती थी उसको देखकर नगदी होने का अंदाजा लगा लिया करते थे। फिर वह सवारी बस में चढ़ती तो वे भीड़ होने के कारण उसे चारों तरफ से घेरकर खड़े हो जाते थे और मौका लगते ही ब्लेड से उसकी जेब काटकर उत्तरकर मौका से फरार हो जाते थे। जब आरोपियों को बस में चढ़ने के दौरान जेब तराश करने का मौका नहीं लगता था तो आरोपी सवारी के साथ बस में चढ़ जाते थे और कड़कर से आगे की टिकट भी ले लेते थे, ताकि उन पर कोई आशंका न कर सके। जैसे ही बस में उन्हें मौका लगता तो जेब से नकदी निकाल फरार हो जाते थे।

सुरेंद्र सिंह वासी करनाल ने सदर थाना में मामला दर्ज कराया था कि छह

अगस्त को सुबह 10 बजे नए बस अड्डा करनाल से वह बस में चढ़ने लगा तो जेब से 50 हजार रुपये निकाल लिए गए।

सदर थाना में सतीश कुमार मित्तल वासी सेक्टर आठ ने मामला दर्ज कराया था कि 24 दिसंबर 2020 को करनाल बस अड्डे पर उसकी जेब से पर्स चोरी कर लिया गया, जिसमें 1100 रुपये की नकदी थी।

थाना सदर में जसबीर सिंह ने मामला दर्ज कराया था कि 24 जनवरी 2020 कोनए बस अड्डे पर उसकी जेब से पर्स चोरी कर लिया, जिसमें सात हजार रुपये थे।

सदर थाना में बरयाम सिंह वासी गांव नेवल ने मामला दर्ज कराया था कि 26 अक्टूबर 2020 को आइटीआई चौक से नया बस अड्डा के बीच बस में उसकी जेब से 20 हजार रुपये निकाल लिए गए।

थाना सदर में सरिंद्र सिंह वासी बसंत बिहार ने मामला दर्ज कराया था कि 26 अक्टूबर 2020 को नए बस अड्डे पर उसकी जेब से 10 हजार 500 रुपये चोरी कर लिए गए।

थाना सदर में जयनारायण वासी गांव पटहेडा ने मामला दर्ज कराया था कि 16 नवंबर 2020 को नए बस अड्डे से बस में चढ़ने के दौरान उसकी जेब से 50 हजार रुपये निकाल लिए गए।

सदर थाना में बलराज वासी पानीपत ने ममला दर्ज कराया था कि नए बस अड्डे पर खाना खाते समय उसकी जेब से 3

नवंबर 2020 को 20 हजार रुपये चोरी कर लिए गए।

इंद्री थाना में रविंद्र सैनी वासी शामगढ़ी ने मामला दर्ज कराया था कि तीन फरवरी 2021 को इंद्री बस अड्डे पर उसकी जेब से 26 हजार रुपये निकाल लिए गए।

इंद्री थाना में सत्यवान वासी टपरियों ने मामला दर्ज कराया था कि सात अक्टूबर 2021 को सब्जी मंडी इंद्री में उसका पर्स चोरी कर लिया, जिसमें सात हजार रुपये थे।

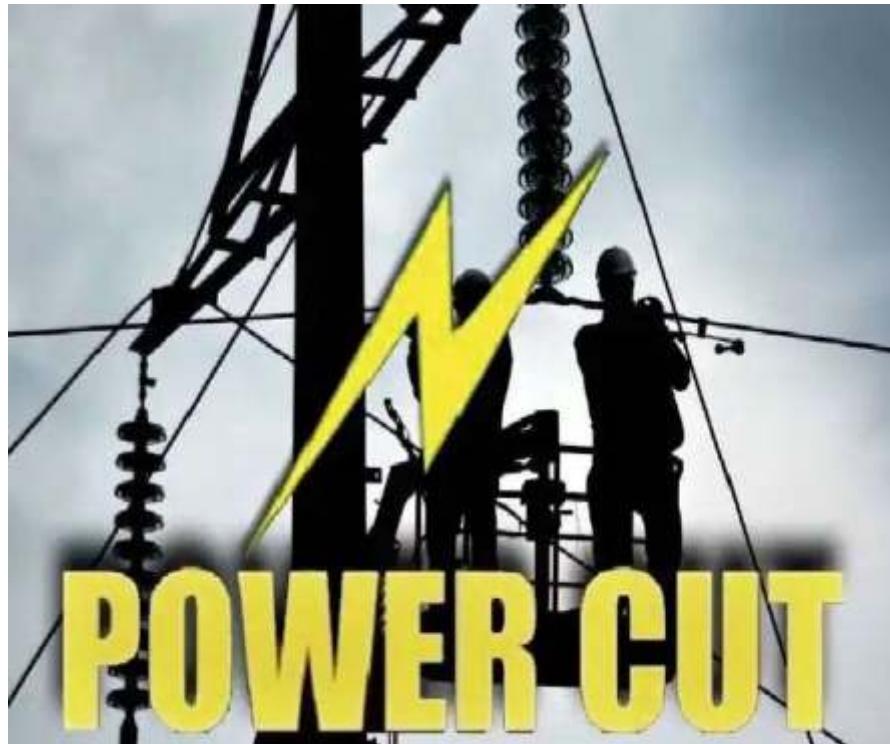
घरौंडा थाना में नितिन वासी घरौंडा ने मामला दर्ज कराया था कि 24 अगस्त 2021 को बैंक में गया था, जहां उसकी जेब से 25 हजार रुपये चोरी कर लिए गए।

सेक्टर 32-33 थाना में सलीम वासी टपराना, सहारनपुर ने मामला दर्ज कराया था कि 28 सितंबर 2021 को मेरठ जाने वाली बस में चढ़ने के दौरान उसकी जेब से 40 हजार रुपये चोरी कर लिए गए।

थाना सिविल लाईन में नन्द किशोर सेक्रेटरी हैफेड ने मामला दर्ज कराया था कि 17 फरवरी 2021 को बस में उसकी जेब से 12 हजार 200 रुपये चोरी कर लिए गए।

थाना सिविल लाईन में विनोद कुमार वासी रामपुरा ने मामला दर्ज कराया था कि एक सितंबर 2021 को देवीलाल चौक से बस में चढ़ने के बाद उसकी जेब से 50 हजार रुपये चोरी कर लिए गए।

क्या कोयले की कमी से उत्तर प्रदेश में पड़ेगा बिजली का संकट



लखनऊ खाज्य व्यूरो। कोयले की कमी से उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट गहराता दिख रहा है। कोयला न होने से सूबे के तापीय बिजली घरों का 7479 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। जल्द कोयले की आपूर्ति सामान्य न हुई तो अन्य यूनिटों के भी बंद होने की आशंका है क्योंकि ज्यादातर बिजली घरों के पास दो-तीन दिन से ज्यादा का

कोयला नहीं बचा है। बिजली की उपलब्धता घटने से राज्य के गांव से लेकर तहसील स्तर तक के कस्बों और बुंदेलखण्ड क्षेत्र में दो से छह घंटे की अतिरिक्त बिजली कटौती हो रही है। कोयले का संकट बना रहा तो बड़े शहरों के निवासियों को भी बिजली कटौती से जूझना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में कुल 18450 मेगावाट तापीय बिजली उत्पादन

की यूनिटें स्थापित हैं लेकिन इन दिनों कोयले की कमी के चलते जहाँ कई यूनिटें ठप हो गई हैं। वहीं अन्य को न्यूनतम क्षमता पर चलाया जा रहा है। पर्याप्त कोयले की आपूर्ति न होने से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की हरदुआगंज, पारीछा, अनपरा का 1220 मेगावाट, एनटीपीसी की सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार, टांडा, मेजा, दादरी व यूपी से बाहर की भी कई यूनिटों का 2428.70 मेगावाट और निजी क्षेत्र की रोजा, ललितपुर, बारा आदि बिजली परियोजनाओं का 3830 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हो गया है।

राज्य के बिजली घरों में से अनपरा व ओबरा के पास ही दो-तीन दिन का

कोयला है। इसी तरह निजी क्षेत्र में अधिकतम तीन दिन तक का ही कोयला बचा है। एनटीपीसी के सिंगरौली व रिहंद को छोड़ अन्य कहीं दो दिन का भी कोयला नहीं है। ऐसे में ज्यादातर यूनिटें न्यूनतम 55 फीसद क्षमता पर ही चलाई जा रही हैं।

गौर करने की बात यह है कि उमसभरी गर्मी के चलते बिजली की मांग जहाँ शेड्यूल के मुताबिक 22 हजार मेगावाट तक है वहीं उपलब्धता लगभग 17 हजार मेगावाट ही है। वैसे तो इनर्जी एक्सचेंज में

पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम

देवराज का कहना है कि गंभीर वित्तीय संकट के चलते कारपोरेशन एक्सचेंज से इतनी महंगी बिजली खरीदने की स्थिति में नहीं है। मांग व उपलब्धता में लगभग पांच हजार मेगावाट का अंतर होने से सूबे के गांवों में चार से छह घंटे की अतिरिक्त कटौती होने से गांवों को लगभग 12-14 घंटे ही बिजली आपूर्ति हो रही है। इसी तरह तहसील स्तर के कस्बों को तकरीबन 18-19 घंटे और बुंदेलखण्ड क्षेत्र में भी 18 घंटे से कम ही बिजली आपूर्ति हो पा रही है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के जिला मुख्यालय व महानगर जहाँ बिजली कटौती से मुक्त हैं वहीं तहसील स्तर के कस्बों को 21.30 घंटे, बुंदेलखण्ड को 20 और गांवों को 18 घंटे बिजली आपूर्ति का शेड्यूल है। बिजली संकट के मद्देनजर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सरकार से आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की है ताकि कारपोरेशन महंगे कोयले व बिजली को खरीद सके।

—एजेंसी

जम्मू कश्मीर: 50 सरपंचों और पंचों का सामूहिक इस्तीफा: बीजेपी की खुली पोल

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के दो ब्लॉकों के करीब 50 सरपंचों और पंचों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों ने वादों के अनुसार सशक्तिरण नहीं करने, अनावश्यक हस्तक्षेप और केंद्र शासित प्रदेश में जनता तक पहुंचने के कार्यक्रमों में प्रशासन द्वारा उनकी अनदेखी किये जाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है, ग्रामीण निकाय में प्रतिनिधियों के इस्तीफे के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, काल्पनिक सामान्य हालात और आंडबर जो दिखाया जा रहा

था उसकी पोल खुल गई है। अधिकारियों ने बताया कि जिला पंचायत अधिकारी अशोक सिंह ने विरोध कर रहे सदस्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और उनसे इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया है और आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायतों का यथा शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि बनिहाल और रामसू ब्लॉक के करीब 50 सरपंचों और पंचों ने शुक्रवार को आपात बैठक के बाद सामूहिक रूप से ब्लॉक विकास परिषद के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

सरपंच गुलाम रसूल मदूर तनवीर अहमद कटोच और मोहम्मद रफीक खान

ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा उनसे किए गए वार्दे अब भी कागजों तक सीमित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी अनदेखी की जा रही है और विकास कार्यों में बेवजह हस्तक्षेप किया जा रहा है जबकि 30 सरकारी विभागों के कार्यों में ग्राम सभा की हिस्सेदारी का वादा क्रूर मजाक साबित हो रहा है।

जनसंपर्क अभियान के तहत हाल में केंद्रीय मंत्रियों के दौरां का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन उनके प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं कर रहा है और केवल चुनिंदा प्रतिनिधियों को ही मंत्रियों से मुलाकात के लिए आमंत्रित किया जा रहा है ताकि सरकार को भ्रमित किया जा सके, पंचों और सरपंचों के दो पन्नों का

इस्तीफा ट्रिवटर पर साझा करते हुए पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने लिखा, 55 पंचों और सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। काल्पनिक समान्य हालत और आंडबर जिसका प्रदर्शन किया जा रहा था, उसकी पोल खुल गई है। सरकार न तो इन जनप्रतिनिधियों को सुरक्षित रख सकी और न ही उन्हें जनकल्याण के लिए सशक्त कर सकी।

उन्होंने कहा, सरकार का जमीनी स्तर तक लोकतंत्र ले जाने के दावे की पोल इन सामूहिक इस्तीफों से खुल गई है। पंचों और सरपंचों की केंद्रीय मंत्रियों के हालिया दौरों के दौरान अनदेखी की गई और प्रशासन उनके साथ सजावट की वस्तुत की तरह व्यवहार करना जारी रखे हुए हैं।

दिल्ली मेट्रो नेटवर्क अब 285 स्टेशनों (नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो, गुडगांव सहित) के साथ लगभग 390 किमी तक फैला



पिंक लाइन को मयूर विहार पॉकेट 1 और शिव विहार स्टेशनों के बीच सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ रहा था।

दिल्ली मेट्रो को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए, अगस्त में त्रिलोकपुरी में इसकी पिंक लाइन के एक छोटे से खंड का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही 38 स्टेशनों तक फैले 59 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क-शिव विहार कॉरिडोर या पिंक लाइन को पहली बार पूरी तरह से जोड़ा गया है। डीएमआरसी के अधिकारियों ने कहा, इस खंड के खुलने के

साथ, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क अब 285 स्टेशनों (नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो, गुडगांव सहित) के साथ लगभग 390 किमी तक फैला है।

इस कॉरिडोर को चौथे चरण में मजलिस पार्क से मौजपुर तक आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे यह लगभग 70 किमी की लंबाई में भारत का सबसे लंबा सिंगल मेट्रो कॉरिडोर बन जाएगा। चौथे चरण के पूरा होने के बाद पिंक लाइन देश में मेट्रो का एकमात्र रिंग कॉरिडोर भी बन जाएगा।

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन-सलमान विवाद की वजह क्या है?

300 मिलियन पाउंड (लगभग 3068 करोड़ रुपये) में न्यूकैसल यूनाइटेड के अधिग्रहण के सौदे का कलब के समर्थकों ने स्वागत किया है। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जुड़े होने के कारण फुटबॉल के कुछ चाहने वाले इससे चिंतित हैं। उनकी चिंता का कारण सऊदी अरब के मानवाधिकारों के रिकॉर्ड को लेकर है।

कलब को सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (पीआईएफ), अरबी स्पोर्ट्स एंड मीडिया और पीसीपी कैपिटल पार्टनर्स ने मिलकर लिया है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के पास है जिसके अध्यक्ष क्राउन प्रिंस सलमान हैं।

हालांकि लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से समर्थित कई उत्पादों का उपयोग करते आ रहे हैं। न्यूकैसल में 80 फीसद हिस्सेदारी लेने वाले पीआईएफ से डिज्नी, उबर, फेसबुक और स्टारबक्स जैसी कुछ कंपनियों ने करोड़ों पाउंड हासिल किए हैं।

पीआईएफ दरअसल सऊदी अरब सरकार के कानूनों के तहत राज्य के स्वामित्व वाला निवेश फंड है। यह अपना अधिकांश पैसा तेल से बनाता है जो सऊदी अरब पूरी दुनिया में बेचता है।

एम्लीयॉन बिजनेस स्कूल में यूरोशियन स्पोर्ट के निदेशक और फुटबॉल फाइनैंस एक्सपर्ट प्रोफेसर साइमन चौड़विक कहते हैं, जो तेल और गैस से प्राप्त होने वाले राजस्व से अलग अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कैसे तेल पर निर्भरता कम करके भी सऊदी अरब की आय होती रहे। कई वो कंपनियां जिनके नाम आप जानते



होंगे। पीआईएफ ने डिज्नी, उबर, फेसबुक, स्टारबक्स और दवा कंपनी फाइजर जैसे कुछ बड़े नामों में निवेश किए हैं। लेकिन साइमन कहते हैं कि पीआईएफ ने इंग्लैंड और उत्तर पूर्व में पवन ऊर्जा में भी भारी निवेश करने की योजना बनाई है।

वे कहते हैं, रूबेन ब्रदर्स (न्यूकैसल अधिग्रहण समूह की एक कंपनी) भी अक्षय ऊर्जा संसाधनों में भारी निवेश कर रहा है।

फुटबॉल कलब का अधिग्रहण इन कंपनियों के शेयरहोल्डर्स के बीच अच्छे संबंध बनाने का मौका देता है।

उनका मानना है कि वो टाइन बंदरगाह और तट से दूर पवन चक्री खेतों में काम करना चाहेंगे। वे कहते हैं, अगर आप लॉन्च टर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो ये संपत्तियां राजस्व पैदा करेंगी।

दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पीआईएफ के अध्यक्ष हैं। 85 साल के किंग सलमान की सेहत ठीक नहीं है और वह पहले ही अपनी ज़्यादातर शक्तियां एमबीएस को दे चुके हैं। यानी 36 वर्षीय प्रिंस सलमान उर्फ एमबीएस ही अपने पिता की सरकार

हालांकि सऊदी अरब सरकार ने हमेशा इस बात से इनकार किया है। इस बीच क्राउन प्रिंस सलमान ने यह दिखाने की कोशिश की कि वे अतिरुद्धिवादी हुक्मत में सुधार कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को ड्राइव करने की अनुमति दी।

कानूनी रूप से बाध्यकारी यह आश्वासन देने के बाद कि सऊदी सरकार

कलब को नियंत्रित नहीं करेगी, प्रीमियर लीग ने न्यूकैसल के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। लगभग 3,068 करोड़ रुपये न्यूकैसल की खरीद पीआईएफ के अरबों रुपये के निवेश का महज एक छोटा सा हिस्सा है।

जिन 15 लोगों पर किया गया खाशोज्जी की हत्या का शक मोहम्मद बिन सलमान ने मार्च 2018 में ब्रिटेन का दौरा किया था। ये तस्वीर उस दौरान प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ ली गई थी।

कुछ लोगों के तर्क हैं कि बड़ी कंपनियों के छोटे हिस्से में निवेश करना प्रीमियर लीग कलब में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने जैसा नहीं है। इस अधिग्रहण पर उठे विवाद के दरम्यान आपने हाल के दिनों में स्पोर्ट्सवाशिंग जैसे शब्द सुने होंगे।

यूएई और कतर जैसे देशों पर हाल ही में ऐसे ही आरोप लगे हैं—उनके बड़े नेता मैन सिटी और पेरिस सेंट जर्मन की मालिक हैं।

दरअसल स्पोर्ट्सवाशिंग शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति, समूह, निगम या राष्ट्र वैश्विक स्तर पर अपनी छवि सुधारने के लिए खेल का उपयोग करती है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि कुछ देश अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड से ध्यान भटकाने के लिए खेल में निवेश करते हैं। महिलाओं के साथ खराब व्यवहार, मौत की सजा का इस्तेमाल और एलजीबीटी विरोधी रुख को इस मानवाधिकार संस्था ने सऊदी अरब के खराब मानवाधिकारों के उदाहरण के रूप में बताया है।

—एंजेंसी

केंद्रीय इस्पात मंत्री की जम्मू में 'इस्पात उपभोक्ताओं' से मुलाकात



केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने जम्मू और कश्मीर में दो दिवसीय सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान कल जम्मू में एक इस्पात उपभोक्ता बैठक को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए, मंत्रीजी ने कहा कि स्टील आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य धारु है, जो निर्माण, बुनियादी ढांचे, रक्षा, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग आदि जैसे उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट सामग्री है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कई नई सड़क और रेल परियोजनाओं के पूर्ण होने पर उद्योग तेजी से बढ़ेगा और इस्पात मंत्रालय की इस्पात कंपनियां आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

माननीय मंत्रीजी ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अपने प्राकृतिक संसाधनों और मेहनती जनशक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र को एक निवेश केंद्र के रूप में पेश करने में की गई पहल की सराहना की। श्री सिंह ने जम्मू-कश्मीर में

स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए एम्स, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों आदि के निर्माण के साथ-साथ, बिजली की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर ध्यान देने की भी सराहना की, जिससे क्षेत्र में स्टील की खपत बड़े पैमाने पर बढ़ाने के अवसर भी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि लेह हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और विस्तार एक सराहनीय कदम है।

अध्यक्ष स्टील अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) श्रीमती सोमा मंडल ने राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न रणनीतिक परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया, जिन्हें

इस क्षेत्र में निष्पादित किया गया है, जिसमें जोजिला सुरंग, जम्मू और कश्मीर में काजीगुंड और बनिहाल को जोड़ने वाली 8-5 किलोमीटर की ऑल-वेदर हाई-टेक सुरंग, अंजीखड़ केबल-स्टे ब्रिज और पाकुल दुल हाइड्रोइलेक्ट्रिक शामिल हैं।

संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, श्री पुनीत कंसल ने सरकार के लिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के महत्व को दोहराया और उद्योग और केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजनाओं के लिए इस्पात की बेहतर उपलब्धता की सुविधा के लिए इस्पात मंत्रालय से पूरी मदद का आश्वासन दिया।

बैठक का आयोजन स्टील अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल द्वारा किया गया था और इसमें जम्मू और कश्मीर सरकार, एसएसआईसी, प्रमुख परियोजनाओं, एमएसएमई और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के डीलरों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।

लखीमपुर : किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने वाला मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्र गिरफतार

लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने के मामले में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्र को मामले की जांच कर ही एसआईटी ने शनिवार देर रात गिरफतार कर जेल भेज दिया है।

उनकी गिरफतारी पर एसआईटी के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा, आशीष मिश्र विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं, इस आधार पर पुलिस उन्हें गिरफतार कर रही है।

हालांकि आशीष मिश्र के वकील अवधेश कुमार सिंह का दावा है कि उनके मुवक्किल ने पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग दिया है। उन्होंने बीबीसी को बताया, घासी जांच हुई है, 150 सवाल पूछे गए थे। हर सवाल के उत्तर लिखित में दिए गए हैं।

शनिवार की देर रात उनका मेडिकल चेक अप पुलिस लाइंस में ही हुआ और उसके बाद उन्हें स्थानीय मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के सामने पेश किया गया, जहां पुलिस ने उन्हें तीन दिन तक रिमांड पर लेने की मांग की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने अगली सुनवाई सोमवार 11 बजे तक स्थगित करते हुए उन्हें लखीमपुर खीरी जेल भेजने का निर्देश दिया।

पुलिस के तीन दिन के रिमांड मांगे जाने से तय है कि पुलिस अभी कई पहलूओं पर आशीष मिश्र से पूछताछ जारी रखना चाहती है। अब सोमवार को एसआईटी की टीम एक बार फिर से आशीष मिश्र को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। आशीष मिश्र के मोबाइल फोन के इस्तेमाल और हादसे के दिन ढाई बजे से चार बजे तक उनकी मौजूदगी के बारे में पुलिस और पूछताछ करना चाहती है।

अब तक हुई पुलिस पूछताछ के बारे में आशीष मिश्र के वकील अवधेश कुमार ने बताया, पुलिस ने पूछा कि दो तारीख की जगह कुश्ती दंगल का आयोजन तीन तारीख को क्यों किया गया, इसका जवाब आशीष मिश्र ने दिया कि मुख्य अतिथि का समय तीन तारीख का मिला था। इसके अलावा यह भी पूछा गया कि इस आयोजन की अनुमति ली गई थी या नहीं, तब आशीष मिश्र ने बताया कि 40 साल से दंगल हो रहा है, अब तक अनुमति की जरूरत नहीं पड़ी थी लिहाजा इस बार भी नहीं ली गई।

बहरहाल, एसआईटी की टीम आशीष मिश्र को तीन दिन के रिमांड पर नहीं ले सकी क्योंकि आशीष मिश्र के वकीलों ने रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी का पक्ष रखने का मौका माँगा और उन्हें वह मौका दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में यूपी पुलिस जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे के साथ पेश आयी है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने संबंधी एफआईआर में आशीष मिश्र पर हत्या, हत्या की साजिश और गैर

इरादतन हत्या के अलावा पांच अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज होने और हत्या जैसे जघन्य अपराध का आरोप लगने के बाद भी पुलिस को आशीष मिश्र की गिरफतारी करने में पांच दिन का समय क्यों लगा और बारह घंटे की पूछताछ की जरूरत क्यों पड़ी?

इस मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम के प्रमुख और लखनऊ डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।

दूसरा सवाल यह भी है कि आशीष मिश्र को गिरफतार करने से पहले दो बार समन क्यों जारी किया गया क्योंकि आम तौर पर हत्या के दूसरे मामलों में अभियुक्तों के लिए समन जारी करने की प्रक्रिया का जिक्र भी नहीं होता है।

उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक विक्रम सिंह ने बताया, समन जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है लेकिन यह इतना हाईप्रोफाइल केस है। इसमें बहुत देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामले पुलिस व्यवस्था के लिए आन-बान की बात होते हैं, ऐसे में पुलिस को फॉर्स्ट फार्मर्वर्ड अंदाज में कार्रवाई करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप कुछ तो संदेश दीजिए कि आप इस मामले पर गंभीर हैं।

आम तौर पर हत्या के किसी मामले की विवेचना में पुलिस शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर सबूत इकट्ठा कर दोष सावित करती है। लेकिन इस हाईप्रोफाइल मामले में, पुलिस ने आरोपी आशीष मिश्र को अपने बचाव में सबूत पेश करने का मौका दिया।

यहां यह भी अहम है कि आशीष मिश्र हत्या के मामले के इकलौते नामजद अभियुक्त हैं ना कि वारदात के चश्मदीद गवाह। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि पुलिस के इस शिष्टाचार की एक वजह आशीष मिश्र के पिता का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होना भी हो सकता है।

आशीष मिश्र स्थानीय पुलिस के सामने पहले समन पर हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद उन्हें दूसरा समन जारी करते हुए शनिवार 11 बजे सुबह तक पहुंचने के लिए वक्त दिया गया था।

विक्रम सिंह कहते हैं, घपले नोटिस पर यह बीमार पड़ गए। यह तो मीडिया का दबाव पड़ा तो यह पेश हो गए, वरना यह और बीमार पड़ते। पुलिस के पास अच्छी सुविधाएँ हैं, अगर यह बीमार पड़े थे तो इनका इलाज लखनऊ के अस्पताल में होता। अच्छे से अच्छा इलाज जेल के अंदर हो सकता है। इस मामले में इतना उदार दृष्टिकोण दिखाना उचित नहीं है।

विपक्ष इस मुद्दे को तूल भी दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, किसानों को कुचलने वाला अभियुक्त गिरफतार जरूर हुआ है लेकिन उनके पिता अभी भी देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनके अधीन पूरे हिंदुस्तान के



सूबों की पुलिस आती है। वे बार बार बोल रहे हैं कि मेरा बेटा बेकसूर है, उसे कलीन चिट दे रहे हैं, ऐसे में उनके अंडर काम करने वाली पुलिस कैसे निष्पक्ष जांच करेगी?

हालांकि इस घटना की जांच से जुड़े तमाम पुलिस अधिकारी पहले दिन से कह रहे थे कि उनकी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था का कायम रखन है, इसलिए विवेचना में विलंब हो रहा है।

राज्य के वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी भी मानते हैं कि पुलिस पर दबाव है।

त्रिपाठी कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस पर सरकार का दबाव है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सबूत के बिना गिरफतारी नहीं होगी। यह संदेह हो सकता है कि क्या मंत्री के बेटे जीप में थे या नहीं या फिर उनकी क्या और कितनी भूमिका है। लेकिन वीडियो से जाहिर है कि गाड़ी बहुत लापरवाही से चलाई गयी थी और वे इकलौते नामजद आरोपी भी हैं, ऐसे में पहले दिन ही गिरफतारी होनी चाहिए थी।

हालांकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हरसंभव कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, लखीमपुर खीरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और एसआईटी जांच कर रही हैं। अभियुक्तों से पूछताछ कर गिरफतारी भी हो गई है। यह योगी सरकार में ही सम्भव है कि एक केंद्रीय मंत्री के बेटे से पूछताछ हुई और फिर गिरफतारी हुई। घटना इतनी बड़ी हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, पुलिस की पहली प्राथमिकता थी कानून व्यवस्था को कायम रखना।

समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्र इस गिरफतारी के बारे में कहते हैं, आशीष मिश्र की गिरफतारी एक तरह से पुलिस के केवल दिखावा है। इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि उनके पिता आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। पुलिस बल खासकर आईपीएस अधिकारियों पर उनके विभाग का जबर्दस्त नियंत्रण होता है इसलिए कोई भी इस मामले में ठीक से जांच कर पाएगा, इसमें हमें ही नहीं तमाम लोगों को संदेह है।

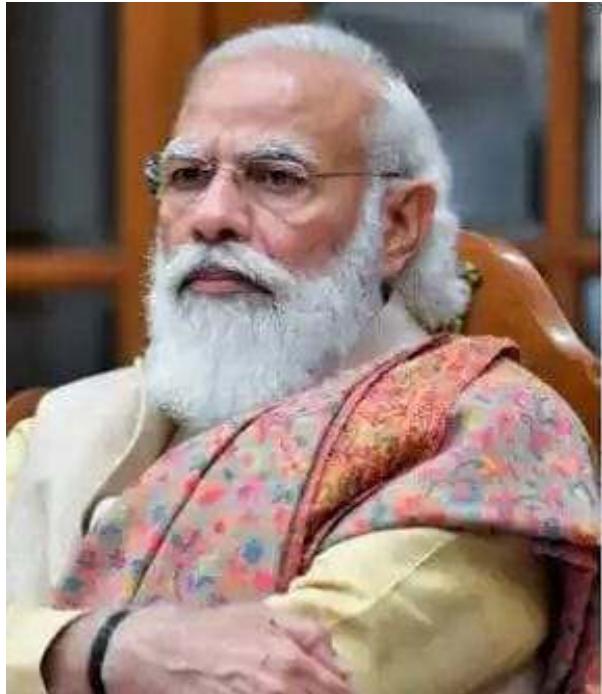
आशीष मिश्र की गिरफतारी के अलावा इस मामले की विवेचना में भी देरी हुई है। पांच दिनों तक घटनास्थल पर मीडिया

टेनी के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल बना हुआ है। हालांकि वे इस घटना के बाद ना केवल वे गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ चुनावी तैयारी संबंधी बैठक में भी हिस्सा ले चुके हैं। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में एक सभा को संबोधित कर चुके हैं लेकिन उन्होंने इस घटना पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

वर्ही दूसरी ओर विपक्ष और मृतक किसानों के परिवारवालों के मुताबिक एक निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री अजय मिश्र टेनी से सरकार को इस्तीफा ले लेना चाहिए।

त्योहारों से पहले कीमत कम करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है सरकार

खाने के तेल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.



सरकार ने 30 सितंबर तक कच्चे पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 30.25 से घटाकर 24.7 फीसदी कर दिया है जबकि रिफाइंड पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 41.25 फीसदी से घटाकर 35.75 फीसदी कर दिया गया है। रिफाइंड सोया तेल और सूरजमुखी तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी भी सितंबर के अंत

तक 45 फीसदी से घटाकर 37.5 फीसदी कर दिया गया है।

उम्मीद है कि इस कटौती का लाभ आम लोगों को मिलेगा और त्योहारों से पहले उन्हें खाने के तेल के लिए कुछ कम खर्च करना पड़ेगा। भारत रसोई तेलों का दुनिया का सबसे बड़े आयातक देश है।



रसोई तेल की जरूरतों को दो तिहाई हिस्सा इंपोर्ट के जरिए ही पूरा ही किया जाता है। ऐसे में तेल के दाम को कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती ही सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है और इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने यह फैसला लिया है।

सरसों तेल को छोड़कर बाकी अन्य तेल को भारत दूसरे देश से आयात करता है। पाम तेल इंडोनेशिया और मलेशिया, सोया और सनफलोवर अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस और यूक्रेन जैसे देशों से आयात किया जाता है। बीते एक साल में खाने के तेल की कीमत 35 से 50 प्रतिशत तक बढ़ी है।

इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के अलावा सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए जमाखोरी को रोकने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने सख्त शब्दों में आदेश दिया है कि खाने के तेल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। वहाँ शुक्रवार को ही केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने व्यापारियों से स्टॉक सीमा लगाने और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय करने की संभावनाओं पर भी चर्चा किया।

अब व्यापारियों और मिलर्स को अपने पास मौजूद तेल और तिलहन का डेटा एक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बाजार में तेलों की उपलब्धता बरकरार रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

—एजेंसी

SUBSCRIPTION FORM TIMES OF PEDIA

Issue	Subscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
--	5,000/-	Life

Name :
Address :

Email:
Contact Phone No.
for donation /life /10 yrs /5 yrs subscription
The sum of Rupees..... (Rs...../-)
through cheque/DD No.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address :
Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I,
Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025
or email : timesofpedia@gmail.com

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi Punjab National Bank, Nanak Pura Branch, New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700



*Ending
Someone's
thirst is
the
Biggest
Deed of
Humanity*

ADVERTISEMENT TARIFF TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

MECHANICAL DATA:

Language: English, Hindi and Urdu

Printing: Front and Back - 4 Colours , Inside pages - B&W

No. of Pages: 12 pages (more in future)

Price: Rs. 3/-

Print order: 25,000

Periodicity: Weekly

Material details: Positives/Format of your advertisements should reach us 10 days before printing.

Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page

Please Add Rs. 10 for outstation cheques.

50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

Bank transactions details of TIMES OF PEDIA

Send your subscriptions/memberships/donations etc.

(Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi

Punjab National Bank, Nanak Pura Branch, New Delhi-110021

A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

प्राकृतिक गैस को लेकर धूरोप के देशों की बढ़ी मुश्किलें

यूरोपीय देश इस समय प्राकृतिक गैस के बड़े संकट का सामने कर रहे हैं। ये देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अधिकतर अक्षय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा प्राकृतिक गैस का है।

लेकिन, यूरोपीय देशों में फिलहाल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है। सर्दियों में ये मांग और बढ़ने वाली है, जिसकी सबसे ज्यादा मार मध्यम और निम्न आयरवर्ग के लोगों पर पड़ सकती है।

प्राकृतिक गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर आना लाजमी है।

ब्रिटेन में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में 10 लाख से भी ज्यादा परिवार अगले साल की शुरुआत में बिजली या अन्य ऊर्जा साधन उपयोग नहीं कर पाएंगे।

ऊर्जा नियामक ऑफिस ने आगाह किया है कि लोगों को अगले साल फिर से उर्जा के दामों में बढ़ोतरी देखनी पड़ सकती है।

पिछले महीने, इस क्षेत्र में काम करने वालीं नौ कंपनियां बंद हो गईं। वो बढ़ते दामों के चलते आई बढ़ती लागत को नहीं छोल पाईं।

यूके स्टील के डायरेक्टर जनरल ग्रेथ स्टेस ने कहा सरकार ऊर्जा कीमतों को काबू करने में विफल हुई है।

इसके साथ ही कीमतों पर लगी सीमा हटाने की बात कही जा रही है ताकि कंपनियों को घाटे के कारण बंद होने से बचाया जा सके।

जर्मनी में भी पावर प्लांट बंद हुए और उसे ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में प्राकृतिक गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है।

किसी देश में ऊर्जा जरूरतों को वर्तमान ही नहीं भविष्य को ध्यान में रखकर भी पूरा किया जाता है। लेकिन, अब अचानक पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। उत्पादन कम है और कीमतें बढ़ रही हैं।

जानकार इसके पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं मानते बल्कि कई वजहों ने मिलकर ये स्थितियां पैदा की हैं।

दुनिया भर में कई कारणों से ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञ इसके पीछे कोरोना महामारी के बाद सामान्य होते जीवन में उत्पाद एवं सेवाओं की बढ़ती मांग, मौसम में बदलाव और कोयले के उत्पादन में आई कमी को जिम्मेदार बताते हैं।

कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्थाएं रुक गई थीं। मांग और उत्पादन दोनों ही कम थे। अर्थव्यवस्थाओं की हालत खराब हो रही थी। लेकिन, महामारी का असर कम होने पर देशों ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आर्थिक सुधार पैकेज दिए।

अमेरिका में आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए खरबों डॉलर का आर्थिक पैकेज दिया गया, जिसका असर अन्य उद्योगों

पर भी देखने को मिला। इसने निर्माण और सेवा उद्योग में तेजी ला दी और यहाँ ऊर्जा की मांग बढ़ गई।

वहीं, कई जगहों पर मौसम में भी बदलाव देखने को मिला है। कई देशों में पिछली सर्दियों में ही मांग बढ़नी शुरू हो गई थी।

जैसे उत्तरी गोलार्ध में आने वाले कई इलाकों में लंबा ठंड का मौसम देखने को मिला, जिससे गर्मी देने वाले बिजली के उपकरण इस्तेमाल होने लगे। पिछली गर्मियों में अमेरिका और यूरोप में गर्म हवाएं चलीं, जिसने एयर कंडिशनर के

उत्पादन बहुत कम हो गया है।

विवेक जैन बताते हैं, ये बदलाव एक लंबे समय में आया है। कोयले और तेल में निवेश करने वाली कंपनियां कम हो गई हैं। पिछले 10 सालों में ये कंपनियां लगभग 66 प्रतिशत रह गई हैं। अगर आप खनिज को निकालने के लिए निवेश नहीं रह रहे हैं और मांग बढ़ जाती है तो असंतुलन पैदा हो जाता है।

भारत और चीन में ऊर्जा की मांग बढ़ी है और ऐसे में यहाँ कोयले से लेकर प्राकृतिक गैस दोनों की खपत बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए चीन ने



इस्तेमाल को बढ़ा दिया। इससे बिजली की खपत भी बढ़ने लगी।

वहीं, कोरोना से बचाव के लिए निजी वाहनों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई जिससे सीएनजी की खपत बढ़ी।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के निदेशक (कॉरपोरेट्स) विवेक जैन कहते हैं, ऐतिहासिक रूप से मांग पहले कभी इतनी नहीं बढ़ी थी। किसी ने इतनी खपत की उम्मीद नहीं की थी। हमेशा एक से दो प्रतिशत मांग ही बढ़ रही थी। आर्थिक सुधार होने से मांग तेजी से बढ़ी है।

वहीं, इसमें एक बड़ा योगदान कोयले के कम उत्पादन का है। अन्य देशों की तरह एशियाई देशों में भी ऊर्जा की खपत और मांग बढ़ी है। चीन और भारत दो ऐसे बड़े देश हैं जो दुनिया की पूरी आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं।

ये दोनों ही देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक कोयले पर निर्भर करते हैं। कोयले के आयात के मामले में चीन दुनिया में नंबर एक पर है और भारत नंबर तीन पर। वहीं, कोयले के उत्पादन के मामले में भी चीन और भारत क्रमशः नंबर एक और दो पर आते हैं।

लेकिन, हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ते कदमों और निवेशकों की कोयला उत्पादन में घटती रुचि ने यहाँ कोयले का उत्पादन कम कर दिया है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया कोयले के विकल्पों पर काम कर रही है। इसके लिए सौर और पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है। ऐसे में निवेशकों की भी कोयले में रुचि कम हो रही है, उन्हें लाभ कम मिल रहा है। इसलिए कोयले का

पहले कोयला उत्पादित करने की बजाय केवल आयात करने का फैसला लिया था। लेकिन मौजूदा स्थिति में वो भी अपनी करीब 90 खदानें शुरू करने वाला है।

यूरोपीय देश अपनी करीब 43 प्रतिशत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर करते हैं। लेकिन, ऊर्जा की बढ़ती मांग के बीच रूस से होने वाली आपूर्ति भी कम हुई है।

रूस से पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय देशों को प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाती है। ये पाइपलाइन यूक्रेन और पोलैंड से होकर जाती है। लेकिन, इन दोनों देशों से रूस के संबंधों ने तनाव होता रहता है।

ऐसे में रूस ने एक पाइपलाइन तैयार की है नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो सीधे जर्मनी तक जाती है। इससे गैस की आपूर्ति बेहतर हो सकती है लेकिन यूरोपीय देशों ने अभी इस पाइपलाइन को मंजूरी नहीं दी है।

अमेरिका भी इस पाइपलाइन का आलोचक रहा है। उसका कहना है कि अगर सीधी पाइपलाइन को मंजूरी दे दी गई तो यूक्रेन और पोलैंड को आर्थिक नुकसान हो सकता है।

पहले भी यूरोप में प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ी है तो रूस ने आपूर्ति को उसके अनुरूप बढ़ाया है। लेकिन, इस साल रूस की सरकारी ऊर्जा उत्पादन कंपनी गेजप्रॉम ने अतिरिक्त आपूर्ति के कम ऑर्डर स्वीकार किए हैं।

इसे रूस के दबाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि यूरोप में ऊर्जा संकट के बीच प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में श्नॉर्ड स्ट्रीम 2 की अहमियत दिखाने की कोशिश है ताकि इसकी मंजूरी आसान हो सके।

हालांकि, रूस इससे इनकार करता है और उसने ऊर्जा आपूर्ति की कमी में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। रूस ने यूरोप में मांग के मुताबिक आपूर्ति बढ़ाने का आश्वासन भी दिया है।

वहीं, रूस में भी ऊर्जा की खपत बढ़ गई है और कोरोना महामारी के दौरान यहाँ भी उत्पादन पर असर पड़ा है।

कई बड़े देशों पर इस ऊर्जा संकट का गंभीर असर देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया इसके प्रभाव से गुजर रही है। ऐसे में क्या इतने बड़े संकट का अंदाजा किसी को नहीं था या कहीं चूक हुई है?

विवेक जैन कहते हैं, ज्योरोना महामारी के दौरान उत्पादन कम होने से कोयले की खदाने बंद की गई। कई खदानें पहले से ही धीरे-धीरे बंद की जा रही थीं। पर जब आप खदान बंद कर देते हैं या उत्पादन घटा देते हैं तो उसे फिर से शुरू करने में या रफतार पकड़ने में समय लगता है।

खनिज पदार्थों के उत्पादन में ऐसा नहीं होता कि आज बंद किया तो कल शुरू कर लेंगे। मान लीजिए आपने दूसरी तिमाही में फैसला किया कि इसे शुरू करना है तो शुरू होते होते ही छह महीने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वैश्विक स्तर पर इसकी जानकारी नहीं थी लेकिन किसी ने इतनी ज्यादा मांग की उम्मीद नहीं की थी।

जानकारों का मानना है कि इस समस्या का तात्कालिक समाधान तो निकाल लिया जाएगा लेकिन दीर्घकालिक उपायों पर भी गैर करना होगा।

विवेक जैन कहते हैं कि कोयला उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है लेकिन इन स्थितियों ने एक बात साफ कर दी है कि कोयले को अपनी जरूरतों से हटाना इतना आसान नहीं है।

वह कहते हैं, ज्योरे में एक समय आएगा जब कोयले और अन्य ऊर्जा संसाधनों के साथ जीना पड़ेगा। अभी हम 100 प्रतिशत शिप्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्राकृतिक गैस का उत्पादन सीमित है और नवकरणीय ऊर्जा की अपनी सीमाएं हैं।

वहीं,

रामविलास का श्रद्धा पूर्वक मनाया गयी प्रथम पुण्यतिथि

औरंगाबाद: (बिहार) दिवंगत, लोक जनशक्ति पार्टी, संस्थापक, पद्मभूषण, पूर्व, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, स्वर्गीय, रामविलास पासवान का प्रथम पुण्य तिथि अलग अलग तरीके से कई स्थानों पर श्रद्धा पूर्वक मनाया गया।

एक तरफ रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी, प्रत्याशी, रह चुके, मनोज कुमार सिंह ने जहां नयी दिल्ली पहुंचकर लोजपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद, माननीय, चिराग पासवान के साथ नयी दिल्ली में अपने दिवंगत नेता की प्रथम पुण्यतिथि में शामिल होकर श्रद्धा पूर्वक उनके तैलिय चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया।

वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद, जिला मुख्यालय में दलित सेना के जिलाध्यक्ष, जितेंद्र पासवान ने मुख्यालय स्थित, लोजपा कार्यालय में लोजपा, प्रवक्ता,



अखिलेश पासवान, नगर अध्यक्ष, राजु पासवान, अलीसाफे अंसारी एवं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक टीम के साथ मनाया।

वही औरंगाबाद जिला के लोजपा जिलाध्यक्ष, अनूप कुमार ठाकुर ने भी ओबरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी, रह चुके डॉ प्रकाश चंद्रा, पूर्व, कुटुंब विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी,

सरुण पासवान, लोजपा, नेता, वीरेंद्र सिंह, नगर परिषद के पूर्व, वार्ड नंबर 07 पार्श्व सह नाई संघ, जिलाध्यक्ष, विनोद ठाकुर एवं अन्य लोजपा नेताओं के साथ मुख्यालय स्थित जननायक कर्पूरी मंच, प्रांगण में द्वीप प्रज्वलित करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर, माल्यार्पण करते हुए अपने दिवंगत नेता सह लोजपा संस्थापक, स्वर्गीय रामविलास पासवान का प्रथम पुण्यतिथि मनाया।

समाचार प्रेषण पूर्व रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी, मनोज कुमार सिंह ने मोबाइल पर जानकारी देते हुए बताया कि नयी दिल्ली में माननीय, चिराग पासवान के साथ दिवंगत नेता सह लोक जनशक्ति पार्टी, संस्थापक, स्वर्गीय, रामविलास पासवान जी के प्रथम पुण्यतिथि में लोजपा नेता, राजू तिवारी, हुलास पाण्डेय, संजय सिंह, प्रणव कुमार, आसिफ खान, कांग्रेस के वरीय नेता, राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनता दल, सुप्रीमो, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, जन अधिकार पार्टी, सुप्रीमो, पप्पू यादव, पूर्व, जहानाबाद, सांसद डॉक्टर, अरुण कुमार सहित कई बड़े नेता भी शामिल होकर श्रद्धा पूर्वक उनके तैलिय चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया।

—अजय कुमार पाण्डेय
बिहार

नेशनल एंटी करपान ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय स्थापना दिवस प्रयागराज में संपन्न



औरंगाबाद (मगध बिहार): नेशनल एंटी करपान ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के विज्ञान परिषद भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन में 24 राज्यों एवं विभिन्न जिलों के लोग शामिल हुए। वही इस सम्मेलन में बेहतर करने वाले राज्य को पुरस्कृत किया गया। प्रथम स्थान पर गुजरात, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश, एवं तृतीय स्थान पर बिहार रहा।

माह-ए-रबी उल अब्वल का शानदार इस्तिकबाल किया जाए: मौलाना खालिद रशीद

लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली नाजिम दारूल उलूम फरंगी महल लखनऊ ने किया। वह आज माह-ए-रबी उल अब्वल के इस्तिकबाल के सिलसिले में दारूल उलूम फरंगी महल में खिताब कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्ल0 के सच्चे सहाबा रजिरों ने अपने चहीते रसूल पाक सल्ल0 की सीरत पर पूरी तरह अमल करके दुनिया के कोने कोने में इस्लाम को फैलाया।

पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजेश शुक्ला ने कहा कि आदित्य पूरे देश स्तर पर अच्छे कार्य किए हैं।

कोरोना वैश्विक महामारी के समय में भी अच्छा कार्य करते हुए अपनी मानवता का परिचय दिखाया था! इसीलिए इन्हें पूरे देश स्तर पर सम्मानित किया गया है। तथा राष्ट्रीय कमेटी के सदस्यों ने अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दिया है। वही मनीष कुमार शरण ने कहा कि आदित्य मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति हैं, आदित्य अपने मेहनत के बदौलत बहुत जल्द संगठन में कामयाबी हासिल किया है। तथा अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हासिल कर चुके हैं। वही डॉ पिंकी पाल ने आदित्य को बधाई देते हुए कहा कि इससे पहले भी अपने मेहनत के बदौलत कई बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। आदित्य पिछले वर्ष भी राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार राज्य में प्रथम स्थान हासिल किए थे। हम सबके लिए गर्व की बात है। जिला अध्यक्ष आशुतोष रंजन आदित्य को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह जिले के लिए हर्ष

की बात है। आदित्य श्रीवास्तव को देश स्तर पर सम्मानित किया गया है। वही बिहार प्रदेश प्रभारी आदित्य श्रीवास्तव ने कहा कि से इस से ज्यादा संगठन में मजबूती के साथ कार्य किए जाएंगे, असहाय जरूरतमंद लोगों को इंसाफ दिलाया जाएगा अगले स्थापना दिवस में बिहार प्रथम स्थान हासिल करने का काम करेगी। कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आदित्य को बधाई दी है जिसमें साउथ प्रदेश उपाध्यक्ष शेख रसूल, झारखंड प्रदेश महासचिव गोविंद कुमार सिंह, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सिंह पाटिल, अनिल बोराणा, पटना प्रमंडल अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, बिना उपाध्याय, नितेश कुमार, सुमित कुमार सिंह, विवेक कुमार, नवीन सिन्हा, सतीश सिंह, पवन कुमार, मोनू कुमार, श्वेता श्रीवास्तव, चंदन कुमार, रागिनी कुमारी, शिखा श्रीवास्तव, नूपुर श्रीवास्तव, चांदनी कुमारी, गुडिया कुमारी, राहुल कुमार, रौनक कुमार, अन्य कई लोगों ने आदित्य को बधाई दिया है।

—विश्वनाथ आनंद

मौलाना फरंगी महली ने कहा कि इस्लामी शरीअत की हिफाजत उस पर अमल करने से होती है।

सहाबा रजिरों ने पूरी अमानत दारी, दियानत दारी, और खुलूस से इस्लामी शरीअत के एक एक हुक्म को सारे मुसलमानों तक पहुंचाया।

खुदा पाक के आखिरी रसूल सल्ल0 के उन सहाबा का इतना बड़ा एहसान क्यामत तक आने वाले तमाम इनसानों पर है। उन्होंने कहा कि खुदा पाक के इन

—आईटीएन

The Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu with the achievers in the fields of literature, music and performing arts from the state of Nagaland, in Dimapur on October 07, 2021.



The Union Home and Cooperation Minister, Shri Amit Shah attends the several public programs in his Parliamentary Constituency Gandhinagar, Gujarat on October 08, 2021.

The Secretary, Textiles, Shri U.P. Singh addressing at an Interactive Webinar on Cotton organised by the Confederation of Indian Textile Industry (CITI) coinciding with the Global Cotton Day and "Azadi Ka Amrit Mahotsav" in New Delhi on October 07, 2021.



The Minister of State for Textiles and Railways, Smt. Darshana Vikram Jardosh addressing at the signing ceremony of an MoU between the Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) and the Ministry of Textiles, Govt. of India on implementation agreement of Indo German technical cooperation project -'Sustainability & Value Added in Cotton Economy', in New Delhi on October 07, 2021

The Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu with the achievers in various fields, in Itanagar, Arunachal Pradesh on October 08, 2021.



The Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu inaugurating the Arunachal Pradesh Legislative Assembly Library, Dorjee Khandu Auditorium and a Paper Recycling Unit at Arunachal Pradesh Legislative Assembly, in Itanagar on October 09, 2021.

The Union Minister for Defence, Shri Rajnath Singh addressing on the occasion of the Indian Coast Guard Investiture Ceremony, in New Delhi on October 09, 2021.



The Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Choubey addressing at the closing ceremony of the 67th Wildlife Week at National Zoological Park, in Delhi on October 08, 2021.

सूसर ने क्यूं बहू को उतारा मौत के घाट

मेरठ में बीती चार अक्टूबर को इंटीरियर डिजाइनर अमित बंसल की आत्महत्या के बाद आपा खो बैठे पिता रामकिशन ने बहू पिंकी की कटर से गर्दन पर वार किए थे। घायल पिंकी ने रविवार को दम तोड़ दिया था। सोमवार को स्वजन ने गढ़मुक्तेश्वर स्थित बृजघाट पर पिंकी का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पिंकी की आठ माह की बेटी के पालन पोषण को लेकर दोनों परिवार विचार-विमर्श करेंगे। हालांकि दादी का कहना है कि अमित की आखिरी निशानी समझकर वे बच्ची को पालेंगे। कानूनविदों की राय में भी माता-पिता के बाद पहला हक दादा-दादी का ही बनता है।

इधर, पिंकी के भाई मोहित गुप्ता का कहना है कि बच्ची को लेकर अमित के परिवार से विचार-विमर्श किया जाएगा। अमित और पिंकी की संपत्ति भी बच्ची के नाम कराई जाएगी, ताकि बच्ची का भविष्य सुरक्षित हो। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि रामकिशन को सजा दिलाने के लिए घटना की सीसीटीवी फुटेज ही काफी है। सीसीटीवी फुटेज में रामकिशन कटर से पिंकी पर वार करते साफ दिखाई



पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि रामकिशन का जेल से निकलना अब मुश्किल है। पुलिस भी सभी साक्ष्य जुटाकर जल्द ही कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करेगी। पिंकी के मायका पक्ष के लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।

मोदीपुरम: विवाहिता ने पति, सास और ननद को निकालकर घर पर कब्जा कर लिया। तीनों घर के अंदर जाने की जिद करते हैं तो विवाहिता कंट्रोल रूम को सूचना देकर पुलिस बुला लेती है। पीड़ित युवक अपनी बहन और मां के साथ

सोमवार को कंकरखेड़ा थाने पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। शामली निवासी युवक ने बताया कि उसकी शादी सात साल पहले शामली क्षेत्र निवासी युवती से हुई थी। दंपती के कोई बच्चा नहीं है। शादी के बाद से ही दंपती में व्यवहार शुरू हो गया। करीब तीन साल पहले विवाहिता शामली में ससुराल से अपने मायके जाकर रहने लगी थी।

करीब एक साल पहले युवक अपनी मां और बहन को लेकर कंकरखेड़ा की हाईवे स्थित एक कालोनी में किराये के मकान में रहने लगा। युवक दवा कंपनी में काम करता है। युवक ने इंस्पेक्टर को बताया कि कुछ दिन पूर्व उसकी पत्नी शामली से कंकरखेड़ा वाले मकान पर पहुंची और जबरन घर में घुस गई। पति समेत ननद और सास को घर से निकाल दिया। अब युवक अपनी बहन और मां के साथ दूसरी जगह किराये पर रह रहा है। विवाहिता ननद का सामान भी नहीं दे रही है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सक्सेना का कहना है कि दंपती को परिवार परामर्श केंद्र में जाने के लिए कहा गया है।

—वेब न्यूज़

भारत के आसमान में बहुत जल्द उड़ती दिखाई देंगे कारें

भारत को जल्द ही आसमान में उड़ती कारें देखना कोई फँटेसी नहीं रहेगा, यह जल्द ही साकार होने वाला है और इस सपने को साकार करने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है वह वह रुम्हम्मदऋफुरकानऋशोएब और उनकी टेक्निकल टीम को जाता है ३.

एशिया की पहली फ्लाइंग कार की निर्माता कम्पनी रुटप्छ ज। | मतवउवइपसपजल (चेन्नई) के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर फुरकान शोएब ने एयरनॉटिकल में इंजीनियरिंग की थी

और वह भारत के वन ऑफ सर्टिफाइड नॉट पायलट हैं।

इस उड़ने वाली कार के मॉडल को ५ वर्ष लन्दन के भसपजमबी मॉचव में भी दिखाया गया ३ उड़यन मंत्री ज्योतिरादित्य राव सिंधिया ने इस खोज के लिए कम्पनी की बहुत सराहना की ३.. लेकिन खोजकर्ता का नाम मेंशन करना ही भूल



गए। भारत के प्रॉमिनेंट न्यूज चौनल जी न्यूज, आजतक, इच दमू, छ्वानि ने कार

लॉन्चिंग की न्यूज दिखाई लेकिन किसी ने भी भारत के इस होनहार युवा इंजीनियर

का नाम मेंशन नहीं किया।

'मम न्यूज पर सुधीर चौधरी ने इस कार का सारा श्रेय "मेक इन इंडिया" के तहत मोदी जी को दे दिया, उसने दस बार "मेक इन इंडिया" कहा लेकिन एक बार भी मुहम्मद फुरकान का नाम नहीं लिया।

लेकिन अमेरिका की वेबसाइट थनजनतम थसपहीज ने मुहम्मद फुरकान का नाम मेंशन करते हुए क्रेडिट भी दिया,, और इस खोज के लिए उसकी काबलियत की बहुत सराहना की।

शायद भारत में मुसलमानों को लेकर गढ़े गए एक मिथ पैंचरपुत्र और पंचर छाप एजेंडा को यह सूट नहीं करता है कि होनहार युवा को उसका नाम मेंशन करके क्रेडिट दे सकें।

पूरे देश को आपकी खोज पर गर्व है, डेफिनेटिली यह मुसलमान यूथ का मोराल अप करेगा और इंस्पायर करेगा।

—आईटीएन

यूपी फ्री लैपटॉप योजना का रेजिस्ट्रेशन जल्द होगा शुरू, ऐसे करें आवेदन



लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए यूपी फ्री लैपटॉप योजना 2021 लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट पास विद्यार्थियों को निशुल्क लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को यूपी फ्री लैपटॉप योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में आएगा। बताया जा रहा है कि इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है।

मिली जानकारी के मुताबिक यूपी फ्री लैपटॉप योजना

से करीब एक करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे। इस योजना का मकसद विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। यूपी फ्री लैपटॉप योजना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए विद्यार्थियों को नचवउव.नच.दपब.पद पर जाना होगा। बताया जा रहा है कि इस योजना का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगा। जिसके बाद इच्छुक विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। बता दें कि इस योजना की विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।